ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाए

कृषि कुंभ (सितंबर, 2023),
खण्ड 03 भाग 04, पृष्ठ संख्या 86–88

ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएँ

स्वपनिल सिंह[1], पूनम सिंह[2] एवं अजय कुमार बहेलिया[3]
शोध छात्रा[1] , सहायक प्राध्यापक[2], एवं शोध छात्र[3]
संसाधन प्रबंधन एवं उपभोक्ता विज्ञान विभाग, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन
[1,2] सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, [3]कृषि महाविद्यालय
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत।
Email Id: swapnilsing7233@gmail.com

मानव की तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती है– रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों आवश्यकताओं देखते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई है।

इन योजनाओं का अनुकरण करके हम अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते है। इन योजनाओं की सहायता से अपने कला कौशल का विकास कर सकते है जैसे– , मोमबत्ती बनाना, अचार–मुरब्बा बनाना, सिलाई–कढ़ाई–बुनाई, टोकरी,चटाई आदि बनाकर आय के स्रोतो को बढ़ा सकते है।

इन योजनाओं की सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि हम कम से कम दर पर कर्ज ले सकते है और अपनी छोटी या बड़ी व्यवसाय की शुरूआत कर सकते हैं इस प्रकार हम अपनी आय को दोगुनी कर सकते है।

सरकारी योजनाएँ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से अब तक कई सरकारी योजनाओं की शुरूआत की है जिसका लाभ भारत की जनता को मिल रहा है।

अब तक लगभग 135 से ज्यादा सरकारी योजनाएं हैं इन्हे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने शुरू की है। कुछ योजनाएं निम्नलिखित है–

1) प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्ध योजना
2) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
3) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
4) प्रधानमंत्री जन–धन योजना
5) आयुष्मान भारत
6) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
7) अटल पेन्शन योजना
8) प्रधानमंत्री सिंचाई योजना
9) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
10) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
11) गोबर धन स्कीम
12) मेक इन इंडिया

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्ध योजना

बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए सुकन्या समृद्ध योजना को केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किया है। सुकन्या समृद्ध योजना केन्द्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जो बेटियों की भविष्य में होने वाले खर्चों की पूर्ति करने में सहायता करेगी। इस योजना को बेटी–पढ़ाओं बेटी–बचाओं योजना के तहत दस वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के माता–पिता इस योजना के अर्न्तगत बालिका का अकाउंट खोल सकते है। इस योजना के अर्न्तगत 250 से शुरू करके 1.5 रूपये निवेश किये जा सकते है।

सुकन्या समृद्ध योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। एक परिवार की केवल दो बेटियों के नाम पर अकाउंट खोला जा सकता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

2015 में शुरू की गयी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमियों को दस लाख तक का ऋण प्रदान करना है और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एम.एफ.आई) के लिए एक नियामक के रूप में कार्य करना है। मुद्रा का लक्ष्य महिला उद्यमियों सहित कुशल श्रमिक और उद्यमी है। यह योजना गैर कार्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्रों को वित्तीय सुविधाओं की पहुँच को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। जो उन्हे जी.डी.पी वृद्धि रोजगार सृजन के साधन में बदल देगी।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभ

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण सुविधा।
- कोई न्यूनतम ऋण राशि नहीं।
- निधि और गैर निधि आधारित आवश्यकताओं के लिए।
- विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण का उपयोग किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का केन्द्रीय बजट 2015–16 के दौरान घोषणा की गई थी। जिसके अर्न्तगत किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने से 2 लाख रूपये और प्रतिवर्ष 436/प्रीमियम का बीमा किया जाएगा। बीमा प्रीमियम खाता धारक के खाते से आटो–डेबिट कर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना

प्रधानमंत्री जन–धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैकिंग सुविधाएं मुहईया कराने और हर परिवार का खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 का भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। 28 अगस्त 2014 को योजना के उद्घाटन के दिन भारत भर में समस्त बैंकों द्वारा एक साथ मिलकर 60 हजार शिविर लगाए गए। परिणामस्वरूप, योजना के पहले दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। समस्त परिवारों को जन–धन योजना में शामिल किया गया। 14 जनवरी 2018 तक 30.97 करोड़ खाते खोले जा चुके है जिसमें 79689.72 करोड़ रूपये की धनराशि जमा है।

आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य कल्याण योजना है यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की गई है। जिसके दो मुख्य स्तम्भ है। देश में 1 लाख हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स स्थापित करना एवं 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ केवल वही परिवार ले सकते है जिनकी मुखिया महिला हो एवं जिनके घरों में 16–59 वर्ष पुरूष सदस्य न हो आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने के लिए व्यक्ति के पास पारिवारिक समग्र आई–डी के साथ (आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि) को जन सेवा केन्द्र पर अपने साथ ले जाए और आयुष्मान कार्ड बनवाये।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों का नुकसान होने पर किसानों को बीमा कवर राशि दी जाती है। इस योजना के अर्न्तगत किसानों से रबी की फसल के लिए 1.5 प्रतिशत खरीफ की फसल के लिए 2 प्रतिशत और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल योजना योजना

की शुरूआत से अब तक 36 करोड़ किसानों का बीमा किया जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक हानि होती है तो इस हानि को सरकार द्वारा कुछ हद तक कवर करने की कोशिश किया जाता है। इस योजना के तहत किसानों के द्वारा की भुगतान की जाने वाली बीमा की प्रीमियम राशि बहुत ही कम रखा गया है। जिससे छोटा किसान भी इस योजना का लाभ उठा सके।

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केन्द्रित एक पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम रूपये की गारण्टी ग्राहको के योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पर 1,000 या 2,000 या 3,000 रूपये प्रतिमाह दिया जाएगा। यह योजना सभी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को 20 वर्ष तक निवेश करना होता है यह निवेश 60 वर्ष के बाद आपको 1,000 से 5,000 रूपये तक मासिक पेंशन दी जाती है।

प्रधानमंत्री सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि में सुधार लाने और देश में संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है वर्ष 2015–2016 की समयावधि में इस योजना में 53 अरब रूपये का बजट आवंटित किया गया है। यह निर्णय 1 जुलाई 2015 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति की बैठक में लिया गया है। जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी।

प्रमुख उद्देश्य

- क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का कार्य पूर्ण करना।
- सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करें।
- पानी की बर्बादी को कम करने के आर्न फार्म जल उपयोग दक्षता में उपयोग करें।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसमें भ्रष्ट लोगों के बैंकों में जमा कराये जाने वाले काले धन को सरकार गरीबों के विकास में लगाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को राशन प्रदान किया गया है। इस योजना को सरकार ने नवम्बर 2020 तक बढ़ा दिया था। इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेंहूँ या चावल बिल्कुल मुफ्त प्रदान किये गए है। वर्तमान समय में इस योजना ने सरकार ने दिसम्बर 2023 तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1 जनवरी 2020 में शुरू की गई है।

गोबर धन स्कीम

गोबर धन स्कीम की शुरूआत पहली बार 1 फरवरी 2018 को वित्त मंत्री अरूण जेटली ने की थी। जिसको अब केन्द्र सरकार के सहयोग से सुचार रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। गोबर धन योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बनाए रखना है तथा इसका उद्देश्य गांवों में गोबर सहित जैव अपशिष्ट के मौजूदा समस्याओं का प्रबंधन और इन्हे बायो गैस एवं जैविक खाद में परिवर्तित करना है। जिससे गांव के किसानों एव परिवारों को आर्थिक और संसाधन का पूर्ण लाभ मिल सके। गोबर धन योजना के माध्यम से गोबर को बायो गैस एवं जैविक खाद में बदलकर रोजगार के अवसर और घरेलू बचत को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

निष्कर्ष–

अतः इस प्रकार से कहा जा सकता है भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम ग्रामीण व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है।